

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /एफ ०३-४१/२०१७/२६-२
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/12/2017

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त संयुक्त / उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.

विषय— “समाधान एक दिन—तत्काल सेवा” व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य— तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन स्वीकृत करने के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

2. पदाधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा —

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड —

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
2. अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों ने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।
3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हुये, अस्थिबाधित जो दोनों पैरा से चलने में असमर्थ, दृष्टिबाधित 40 प्रतिशत से अधिक, श्रवण बाधित 40 प्रतिशत से अधिक, मंदबुद्धि जिनको चिकित्सकों द्वारा प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।
4. निःशक्त विद्यार्थी का नाम समग्र स्पर्श पोर्टल में अंकित होना चाहिये।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया—

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1	विगत वर्ष में उत्तर्ण परीक्षा की अंक—सूची।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
2	चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण—पत्र।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अथवा स्पर्श पोर्टल (sparsh.samagra.gov.in) से
3	शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल,	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार

	महाविद्यालय अथवा पॉलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र।	पर
4	आवेदक/आवेदिका के पासपोर्ट साईज का एक फोटोग्राफ	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
5	आवेदक/आवेदिका का आधार की छायाप्रति (यदि हो तो)	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
6	आवेदक/आवेदिका का समग्र आई.डी.	सत्यापन समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) से

5. आवेदन करने का स्थान— लोक सेवा केंद्र

6. आवेदन करने की प्रक्रिया –

6.1 पात्रता अनुसार पूर्ण दस्तावेज सहित आवेदन लोक सेवा केंद्र में स्वीकार किये जायेंगे।

6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।

6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जावेगी।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक/अन्य किसी संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नम्बर भरना अनिवार्य होगा, इसके अलावा अगर आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा।

7. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया –

7.1 लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा आवेदन संबिठ करते ही आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।

7.2 पदाभिहित अधिकारी द्वारा कंडिका 4 अनुसार पात्रता एवं दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा।

7.3 यदि आवेदक पात्र है तो पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर स्वीकृति आदेश जारी करते हुए स्वीकृति आदेश की प्रति **mpedistrict** पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

7.4 यदि आवेदक अपात्र है तो अपात्रता का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

7.5 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजिटरी वेबसाईट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी।

8. अपीलः— समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अपील कर सकेगा।

9. रिमार्कः— योजनान्तर्गत प्रदाय लाभ की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु विभाग द्वारा पूर्व से अधिकृत विभागीय संस्था/अधिकारी लोक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त कार्य करते रहेंगे।


(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 23/12/2017

पृ.क्र./एफ ०३-५१/२०१७/२६-२

प्रतिलिपि :-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन, भोपाल।
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म.प्र. भोपाल।
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायती राज संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, विध्याचल भवन भोपाल।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।


अवर सचिव

म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण विभाग